

सेवा,

शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

मेला में,

शिक्षा निदेशक,
जयपुर, राजस्थान/ जयपुर।

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा,
जयपुर, जयपुर।

विषय 111 अनुभाग

तकनीक दिनांक 21 मार्च, 1984

विषय: राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों की अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा विस्तारण।
महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक अनुभाग-2 के अध्यापक-1/2/1973-शर्मांक-2, दिनांक 23 मई, 1983 में सुस्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा-विस्तार/गुननिपुणता/अनुवन्ध के आधार पर अध्यापक पदों पर नियुक्ति स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2- इस संबंध में शिक्षा विभाग की विशेष कठिनाइयाँ शासन के समक्ष आई हैं कि राजकीय शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक क्षेत्र के मध्य में सेवा-निवृत्त होने से न केवल शैक्षिक संस्थाओं में संबंधित विषय के अध्यापन का कार्य कुछ समय के लिये अस्त-व्यस्त हो जाता है अपितु उनके स्थान पर जो नये अध्यापक आते हैं उनके लिये भी पूर्ण गति से कार्य करने में कुछ समय लग जाता है इसके कारण शिक्षण कार्य में एक लम्बी अवधि के लिये दिक्कत आ जाती है, तथा दूसरी ओर जिन संस्थाओं से अध्यापकों के स्थानान्तरण अथवा प्रोन्नति द्वारा इस प्रकार की रिक्तियाँ भरी जाती हैं उनमें भी शैक्षिक कार्य में अक्षय उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार कई विद्यालयों के शिक्षण कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है और छात्रों की पढ़ाई में व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है।

3- उपरोक्त कठिनाइयों पर सम्पर्क सम से विचारोपरान्त पार्श्वमूर्ति शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए राजस्थान महोदय जनहिता में वित्तीय हस्तक्षेपितका छड-2

1. नं. 8196/15-1-31 11/61/77 दि. 8-2-1970 भाग-2 से 4 के मूल

2. नं. 12429/15-2-27 11/76 दि. 12-5-1977 नियम 56।ए। के

3. नं. 318/15-2-77-30 11/61/71 दि. 6-2-78 अन्तर्गत यह आदेश देते

हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को जो शिक्षा क्षेत्र के मध्य में अर्थात् 1 जुलाई के बाद और 30 जून से पहले अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष प्राप्त कर रहे हों, को निम्नान्वित शर्तों पर संबंधित शैक्षिक क्षेत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक सेवा विस्तारण दे दिया जाय :-

1- सेवा काल में संबंधित अध्यापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का कार्य एवं आचरण सतीषजनक रहा हो।

2- वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ हो।

3- यह वास्तव में कोई विधायन नियमित स्म से पढ़ाता हो । 3. प्रचार के सभी मामले उत्पादेश के लिये समय से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना तथा प्रत्येक के संबंध में शासन के आदेश प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

4- मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन का कार्य न कर रहे हों उनकी सेवा में अन्तिम वर्ष अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय जिससे उन्हें अनायास ही 30 जून तक सेवा में बने रहने का लाभ मिल जाय ।

5- मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के शिक्षा - 14 अनुभाग के शासनादेश नं०- 1772/15-14-301671/71, दिनांक 6-5-1982 संपठित शासनादेश संख्या 2974/15-14-301671/71, दिनांक 26-7-1983 में जारी किये गये आदेशानुसार राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कृत अध्यापकों को जो शारीरिक एवं मानसिक स्म से पूर्णतया स्वस्थ हैं, उनकी अधिपथता आयु के पश्चात् दो वर्ष के सेवा विस्तार की सुविधा प्रदान की गयी है। यह सुविधि राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को पूर्ववत् जारी रहेगी ।

6- राजपाल महोदय जनहित में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 56-1ए1 के अन्तर्गत यह भी आदेश देते हैं कि शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत सभी राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को जो शिक्षा सत्र के मध्य में अर्थात् 1 जुलाई के बाद जिनका 30 जून के पहले 60 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, को उपर्युक्त परिच्छेद-3 में उल्लिखित शर्तों पर ही 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक सेवा विस्तार प्रदान किया जाय । इन मामलों में भी यह आवश्यक होगा कि ऐसे अधिकारियों को जो अध्यापन कार्य न कर रहे हों उनकी सेवा के अन्तिम वर्ष में अध्यापन के कार्य में बिना किसी विशेष कारण के न लगाया जाय ।

यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भारतीय,

ह0/- ज्ञान चन्द्र जैन
संपुक्त सचिव।

प्र0 संख्या 7022/15-1-84-31/161277 तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त प्रभुनाथराय राजकीय डिग्री/पास्ड केजरी कालेज, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जिला प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला वैदिक शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त अतिरिक्त जिला वैदिक शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
10. कार्मिक अनुभाग-2

आज्ञा से,

प्रमाणित
ह0/ सुशील चन्द्र सक्सेना

ह0/ ज्ञान चन्द्र जैन
संपुक्त सचिव।

अनुभाग अधिकारी, शिक्षा 111 अनुभाग,
उ0प्र0 सचिवालय।

सं. सं. ००००००

संख्या 7704 / उच्चोत्तर-1-90-2जो 1508/89

सेवा में,

के. आर. ओ. भाटो
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. निदेशक,
जनजाति विकास, 3090,
लखनऊ।

अ. म.
205 म. 201 1/2
4-2-01

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 21 जनवरी, 1991

विषय:

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन के शिक्षा अनुभाग-1 से जारी शासनादेश

संख्या 7022/158183-3188/77, दिनांक 21 मार्च, 1984 को प्रतिलिपि संलग्न करके भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि संदर्भित शासनादेश द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को शिक्षा सत्र के मध्य में अर्थात् पहली जुलाई के बाद और 30 जून, के पहले अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने की दशा में कुछ शर्तों पर संबंधित शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् आगामी 30 जून तक सेवा विस्तारण दिया गया है ; अतः शासन के सभी विभागों में समस्त बचाये रखने के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि हरिजन एवं समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग के अधीनस्थ राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्ति के बारे में भी शिक्षा विभाग से जारी संदर्भित शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 1984 में निर्धारित प्रक्रिया एवं नीति को लागू कर दिया जाय।

2- तदनुसार अग्रे शाब्दनादेश संख्या-454/36-7080-60/74 दिनांक 5-8-1975 द्वारा जारी किये गये निर्देश स्वतः संशोधित हो गये हैं और नयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें और अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को इससे अवगत करा दें।

भवदीय,

के० आर० भाटो
सचिव।

पू०सं०-7704 §1§/छद्मबोस-1-90 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- §1§ समस्त मण्डलीय उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ०प्र०
- §2§ प्रधानाचार्य, राजकीय गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेक्निक, लखनऊ।
- §3§ प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ/गोरखपुर/मैनोताल।
- §4§ महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- §5§ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- §6§ कोषाधिकारी, लखनऊ/गोरखपुर/मैनोताल।
- §7§ समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- §8§ हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-2/3।
- §9§ स्पेशल कम्पोजेन्ट प्लान।
- §10§ आई०सी०डी०रस०सेल।
- §11§ गार्डफ़ाइल।

जमा है,

§1§
विशेष कोषाधिकारी।

सेवा विस्तरण में आंशिक संशोधन

संख्या-2414/26-1-2015-2जी (150)/89

प्रेषक,

सुनील कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक, समाज कल्याण /

जनजाति विकास विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 17 अगस्त, 2015

विषय- समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं, प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा विस्तरण (सत्रलाभ) विषयक निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 276/स0क0/स्था0-2/258/वे0-विस्तारित/2015-16 दिनांक 26 जून 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-7704/26-1-90-2जी (150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को शैक्षिक सत्र के मध्य अर्थात् 01 अप्रैल के बाद और 31 मार्च के पहले अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की दशा में शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र के अन्त तक अर्थात् 31 मार्च तक सेवा विस्तरण का लाभ अनुनयन किये जाने हेतु यथोचित निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

- 2-- उल्लेखनीय है कि शिक्षा सत्र मध्य अर्थात् पहली जुलाई के बाद और 30 जून के पहले अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या -7022/15-1-84-31(18)/77, दिनांक 21.03.1984 में उल्लिखित सेवा शर्तों के अनुरूप समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को सेवा विस्तरण/सत्रलाभ की सुविधा शासनादेश संख्या-7704/26-1-10-2जी(150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 द्वारा प्रदान की गयी तथा कालान्तर में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के अधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को भी उक्त सुविधा शासनादेश संख्या-5717/26-1-95-2जी(150)/89 दिनांक 19 जनवरी 1996 द्वारा प्रदान की गयी शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-1289/15-7-2014 दिनांक 15.10.2014 द्वारा

शैक्षिक सत्र माह पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर पहली अप्रैल से 31 मार्च किया गया जिसके क्रम में समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 648/26/- 3-2015-10(1)/2015 दिनांक 25 मार्च 2015 द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों / संस्थाओं हेतु शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि निर्धारित किया जा चुका है।

- 3- अतएव समाज कल्याण तथा जनजाति विकास विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों प्रवक्ताओं प्रधानाध्यापकों तथा प्राधानाचार्या एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों को अधिवर्षता आयु के पश्चात सेवा विस्तारण (सत्रलाभ) संबंधी शासनादेश संख्या-7704/26-1-90-2जी(150)/89 दिनांक 21 जनवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या-5717/26-1-95-2जी(150)/89 दिनांक 19 जनवरी 1996 में शैक्षिक सत्र पहली जुलाई से 30 जून के स्थान पर शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च समझा जाय।
- 4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवा विस्तारण/सत्रलाभ प्रकरणों को पूर्व सेवा शर्तों के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्धारित नवीन शैक्षिक सत्र के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0अ0

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव